

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2776

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता में वृद्धि

2776. श्री सालिम अन्सारी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का अपनी क्षमता को 6000 मेगावाट से बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसकी क्षमता में वर्ष-वार कितनी बढ़ोतरी हुई और भेल की वर्तमान क्षमता क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि भेल सोलर फोटो-वोल्टिक सिस्टम के विनिर्माण हेतु महाराष्ट्र में एकीकृत सुविधा स्थापित कर रहा है, एडवान्सड अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और 700 मेगावाट के परमाणु संयंत्रों के कार्यनिष्पादन के लिए एनपीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी) बना रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति के साथ भेल द्वारा शुरू की गई इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

(क) और (ख): भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मुख्य विद्युत संयंत्र उपकरण की सुपुर्दगी के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान अपनी क्षमता 6000 मेगावाट प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 मेगावाट प्रति वर्ष के स्तर तक पहले ही कर ली है। तदनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य विद्युत संयंत्र उपकरण की सुपुर्दगी के लिए बीएचईएल की मौजूदा क्षमता मार्च, 2012 के पश्चात् 20,000 मेगावाट प्रति वर्ष के उसी स्तर पर है।

(ग) और (घ): ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना/पहल	स्कीम/परियोजना/पहल का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति
1.	सोलर फोटो-वोल्टिक सिस्टम के विनिर्माण हेतु महाराष्ट्र में एकीकृत सुविधा	भेल राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के अंतर्गत 40% पूंजी सब्सिडी तथा अन्य सब्सिडियां प्रदान करने की शर्त के अध्यक्षीन महाराष्ट्र में चरणबद्ध रूप से लगभग 480 मेगावाट प्रति वर्ष की एकीकृत सोलर फोटो-वोल्टिक (पीवी) विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है। आवश्यक अनुमोदन और मंजूरियां, मंत्रिमंडल की ओर से भी, की उपलब्धता से लगभग 36 माह में चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए विनिर्माण सुविधा की योजना बनाई गई है। इस संबंध में, एनसीईएफ के अंतर्गत 40% पूंजी सब्सिडी का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।
2.	एडवान्सड अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना।	भेल ने इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में 'थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एडवान्सड अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल (एडवांस्ड-यूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास' शुरू किया है। इसका उद्देश्य थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एडवांस्ड-यूएससी प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य पहलुओं की शुरुआत करना है ताकि पावर प्लांट दक्षता में सुधार (45-46% तक), कार्बन-डाई ऑक्साइड उत्सर्जनों में कमी और कोयले की खपत में कमी करने के साथ-साथ विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित 800 मेगावाट क्षमता का एक नमूना पावर प्लांट स्थापित किया जा सके। इस संबंध में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) का कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्त से कतिपय परियोजना-पूर्व अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त संघ ने परियोजना के अनुसंधान एवं विकास चरण के लिए भारत सरकार से अनुदान सहायता के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है और यह प्रक्रियाधीन है।
3.	700 मेगावाट के नाभिकीय संयंत्रों के निष्पादन के लिए एनपीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन।	भेल, फिलहाल 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) आधारित नाभिकीय पावर प्लांट के परंपरागत आइलैंड के इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) क्रियाकलाप शुरू करने के लिए एक त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन करने के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और मैसर्स एल्सटॉम के साथ वार्ता कर रही है। पार्टियों के मध्य विभिन्न करारों की निबंधनों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आवश्यक अनुमोदनों के पश्चात् जेवीसी का गठन किया जाएगा।